सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह है 'बृहस्पति': शोध अध्ययन

एक नए शोध के अनुसार, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे पुराना ग्रह भी है।

- वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विशाल ग्रह का निर्माण सूर्य के निर्माण के 40 लाख वर्ष के भीतर ही हो गया था।
- अमेरिका स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी के अनुसार, 'धरती, मंगल, चांद और क्षुद्र ग्रहों की तरह बृहस्पति का कोई सैंपल हमारे पास नहीं है।
- हम विभिन्न उल्का पिंडों के समस्थानिकों के आधार पर बृहस्पति की उम्र का अनुमान लगाते हैं।
- इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह है।
- वैज्ञानिकों ने कहा कि यह बेहद विशाल ग्रह है और इसकी उपस्थिति से सौरमंडल की कई गतिविधियां निर्धारित होती हैं।

र्राष्ट्रीय खबर

इज़राइल के लेखक डेविड ग्रॉसमैन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित

इजराइल के लेखक डेविड ग्रॉसमैन को 14 जून 2017 को उनके नवीनतम उपन्यास 'ए हार्स वॉक्स इनटू ए बार' के लिए लंदन में 2017 का प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार हेतु चयनित किया गया।

- ग्रॉसमैन ने अमोस ओज़ और पुरस्कार के चार अन्य दावेदारों को, जिसे विदेशी भाषा के उपन्यास लेखकों को अंग्रेजी में अनुवादित करने के लिए सम्मानित किया जाता है, को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया।
- मैन बुकर पुरस्कार में 50 हजार पाउंड की राशि दी जाती है।
- यह राशि इस बार ग्रॉसमैन और अनुवादक जेसिका कोहेन में बराबर बंटेगी।
- पहले यह पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता था लेकिन पिछले वर्ष से इसे किसी पुस्तक के लिए दिया जाने लगा।
- वर्ष 2016 में यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया के हानकांग को उनकी रचना 'द वेजीटेरियन' के लिए दिया गया था।

अंतरराष्ट्रीय खबर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (आईडीसीएफ) का शुभारंभ किया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 जून 2017 को अतिसार के कारण बच्चों की मौत की घटनायें को रोकने के सघन प्रयास हेतु सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (आईडीसीएफ) का शुभारंभ किया।

- मंत्रालय ने बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर को विश्व के स्वास्थ्य स्तर के समान लाने के लिए इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी इस पहल के माध्यम से दस्त के नियत्रंण में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को दस्त के नियंत्रण में निवेश को वरीयता देगा।
- पखवाडे के दौरान गांव, जिला और राज्य स्तर पर स्वच्छता के लिए गहन समुदाय जागरूकता अभियान और ओआरएस एवं जींक थेरेपी का प्रचार किया जाएगा।

र्राष्ट्रीय खबर

नीरू चड्ढा इंटरनेशनल सी ट्रिब्यूनल की पहली भारतीय महिला जज बनीं

नीरू चड्ढा को 14 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था 'इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी' (आईटीएलओएस) का न्यायाधीश चयनित किया गया।

- वे इस 21 सदस्यीय अदालत में स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश हैं।
- नीरू चड्ढा को अगले नौ वर्ष के लिए 'इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी' (आईटीएलओएस) की न्यायाधीश निर्वाचित की गयीं।
- नीरू चड्ढा को एशिया प्रशांत समूह में सर्वाधिक 120 मत मिले।
- इस समूह से वह एकमात्र उम्मीदवार थीं, जिन्होंने मतदान के पहले चरण में ही चुनाव जीत लिया। इसी चुनाव प्रक्रिया में इंडोनेशिया के उम्मीदवार को 58, लेबनान के उम्मीदवार को 60 और थाईलैंड के उम्मीदवार को 86 मत मिले।
- इन सभी तीनों उम्मीदवारों ने मतदान के दूसरे चरण में प्रवेश किया जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में अन्य सीट पर थाईलैंड को जीत मिली।
- कुल सात सीटों के लिए मतदान हुआ किया गया तथा इस मतदान में 168 देशों ने भाग लिया।

र्राष्ट्रीय खबर

अजायब सिंह भट्टी पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चयनित

अजायब सिंह भट्टी को 16 जून 2017 पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया।

- उन्हें सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में चुना गया।
- भट्टी पिछले तीन बार से लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।
- कांग्रेस विधायक अजायब सिंह भट्टी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था।
- मुख्यमंत्री द्वारा नाम प्रस्तावित करने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया।
- सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भट्टी को सदन चलाने में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया।
- भट्टी ने विधानसभा डिप्टी स्पीकर चुनने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया।
- पैंसठ वर्षीय भट्टी ने वर्ष 2007 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। वे बठिंडा के रहने वाले हैं।
- वे मलौत क्षेत्र से एमएलए हैं। उन्होंने यह सीट हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जीती है।
- इससे पहले वे बठिंडा में भुचो नामक सीट पर भी 2007 और 2012 में चुनाव जीत चुके हैं।

नियुक्ति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पहले से हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

- भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बांग्लादेश के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग के बीच अप्रैल 2017 में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति द्वारा इसके प्रभावी रहने के दौरान किसी समय इस समझौते का विस्तार हो सकेगा।
- किसी एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को छह माह की लिखित पूर्व-सूचना के बाद इसे निरस्त किया जा सकेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से जुड़ा यह समझौता स्वाभाविक तौर पर एक तकनीकी समझौता है और यह मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, ई-पब्लिक सर्विस डिलीवरी, साइबर सुरक्षा आदि पर जोर देता है।

अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट का पीवी प्लांट स्थापित किया

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्यरत अडानी ग्रुप ने जून 2017 के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 50 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्लांट स्थापित किये जाने की घोषणा की।

- इस प्लांट को राष्ट्रीय सोलर मिशन योजना के तहत 315 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया गया है।
- यह प्लांट क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मोड्यूल से स्ट्रिंग इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोलर पावर उत्पादित करता है।
- एनटीपीसी के साथ हुए एक समझौते के अनुसार इस प्लांट से पैदा हुई उर्जा को 21।5 किलोमीटर दूर स्थित 132 किलोवाट के सबस्टेशन में भेजा जायेगा।
- इस परियोजना से लगभग 250 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- महोबा प्लांट से पूर्व अडानी ग्रुप ने भटिंडा में 100 मेगावाट, गुजरात के बित्ता में 40 मेगावाट तथा हाल ही में तमिलनाडु में 648 मेगावाट के प्लांट स्थापित किये।
- अडानी ग्रुप द्वारा कुल 838 मेगावाट तक की सोलर एनर्जी पैदा की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन.भगवती का 15 जून 2017 को निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। पी.एन. भगवती देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे।

- न्यायिक क्षेत्र में पी।एन। भगवती ने पीआईएल यानी जनहित याचिका को लागू कर काफी ख्याति पाई थी।
- जस्टिस भगवती ने वर्ष 1986 में ही व्यवस्था दी थी कि मौलिक अधिकारों के मामले में कोई भी व्यक्ति सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
- उन्होंने वर्ष 1978 का मेनका गांधी पासपोर्ट कुर्की मामले में जीने के अधिकार की व्याख्या की थी।

- जस्टिस भगवती ने व्यवस्था दी की व्यक्ति का आवगमन नहीं रोका जा सकता।
- पासपोर्ट रखने का अधिकार हर किसी को है।
- कैदियों को मौलिक अधिकार दिए जाने की वकाल भी जस्टिस भगवती ने की थी।